



सम्पादकीय

ओबीसी को लेकर मोदी सरकार को घेर रहे राहुल

आज राहुल गांधी जो भी सवाल उठाते हैं उनसे पूर्ण की कांग्रेस सरकार पर भी सवाल उठ जाते हैं। राहुल गांधी को यह भी खान रखना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री ननेद्र मोदी खुद ओबीसी से संबद्ध है और गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में सहल गांधी को जबाब दे ही चुके हैं कि देश को सचिव नहीं बल्कि सरकार बताती है और मोदी सरकार के संबंधों में ओबीसी की संख्या कांग्रेस के कुल सांसदों से ज्यादा है। अमित शाह ने बताया था कि मोदी सरकार में 29 फॉसटो यानि 85 सांसद ओबीसी हैं और 29 केंद्रीय मंत्री भी ओबीसी से ही संबद्ध हैं।

का

ग्रेस नेता राहुल गांधी बिना किसी तथ्य के मोदी सरकार पर तमाम मुद्दों को लेकर हमसे बोलते हैं। इसी कही में आजकल वह जाति जनगणना की मांग करते हुए मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि देश को चला रहे अधिकारियों में मात्र तीन केंद्रीय सचिव ही ओबीसी समुदाय से हैं। ऐसे में यह जाने वेद जरूरी हो जाता है कि इस मामले में कांग्रेस का अपना खुद का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? इस मामले के देखे तो कांग्रेस चार राज्यों-छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झज्जर क्षेत्र में प्रभुत्व सकार चला रहा है। इन चारों ही राज्यों में सुख्ख सचिव समाज्य श्रेणी से संबद्ध हैं। इसी प्रकार यदि हाल कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों वाले विषयी गठबंधन इडिया पर नजर दौड़ाएं तो पाएंगे कि वहां भी ओबीसी के ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और केरल के सुख्ख सचिव भी अपर कास्ट से संबद्ध हैं। जबकि तरिनामदु एकमात्र एया उदाहरण है जहां सुख्ख सचिव शिव दास माया एसटी श्रेणी से संबद्ध हैं। यही नहीं, सरकारी खंडकाल के अधिक अनुसंधान विभाग द्वारा जारी एक प्रतिवेदन में बताया गया है कि भारत के परिवारों में हाल ही के समय में वित्तीय बचत की दर कुछ कम होकर परिवारों द्वारा भौतिक अस्तियों के रूप में की गई बचत में अनुलेनी वृद्धि दृष्टिगत हुई है। भारत में परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत जो दर्ज एवं राज्य सकारात्मकों द्वारा भौतिक संस्थानों के लिए आय का मुख्य साधन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में पिछले सकल घेरेलू उत्पाद का 5.1 प्रतिशत हड्ड गई है। यह बचत रट वित्तीय वर्ष 2020-21 में 11.5 प्रतिशत एवं कोरोना महामारी खंडकाल के पूर्व वित्तीय वर्ष 2019-20 में 7.6 प्रतिशत थी। ऐसा कहा जा रहा है कि परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत दर पिछले 50 वर्षों के खंडकाल में सबसे कम दर है। परंतु, यह वर्ष सही नहीं है, क्योंकि परिवारों की बचत दर को वित्तीय बचत एवं भौतिक अस्तियों की रूप में की गई बचत को मिलाकर देखा जाना चाहिए। वित्तीय बचत दर वित्तीय वर्ष 2020-21 में कम इसलिए हो सकती है, क्योंकि परिवारों द्वारा उस वर्ष में भौतिक अस्तियों के रूप में अधिक मात्रा में बचत की गई हो। कोरोना महामारी के चलते एक तो कई परिवारों की आय में कमी दर्ज हुई एवं कई परिवारों की पूर्ण खंडकाल के दौरान भारतीय परिवारों का वृद्धि दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है।



प्रकाश सवनानी

कोरोना महामारी के चलते एक तो कई परिवारों की आय में कमी दर्ज हुई एवं कई परिवारों की तो केंद्र में सत चिव्व एसटी श्रेणी और पांच एसटी श्रेणी से हैं। इसी प्रकार यदि हम 2014 के आंकड़ों पर उन नजर दौड़ाएं तो उस समय केंद्र में अतिरिक्त सचिव और संयुक्त-सचिव पद पर ओबीसी समुदाय से संबद्ध हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि इसको बदल देखे तो केंद्र में सत चिव्व एसटी श्रेणी से हैं। यहां एक बात और समझने की जरूरत है कि जहां तक केंद्र सरकार के पदों में ओबीसी को आरक्षण की बात है तो यह 1993 में पेश किया गया था और इसके तहत पहली नियुक्ति पाने वाले अधिकारीयों 1995 बैच के थे जोकि अब तक सचिव रैंक तक नहीं पहुंचे हैं। देखा जाये तो किसी भी आर्जेस्ट अधिकारी थीं जोना करियर शुरू करने से लेकर केंद्र में सचिव पद पर काम करने वाले सभी अधिकारी योग्यांशी से ही थे। यहां एक बात और समझने की जरूरत है कि जहां तक केंद्र सरकार के पदों में ओबीसी को आरक्षण की बात है तो यह 1993 में पेश किया गया था और इसके तहत पहली नियुक्ति पाने वाले अधिकारीयों 1995 बैच के थे जोकि अब तक सचिव रैंक तक नहीं पहुंचे हैं। देखा जाये तो किसी भी आर्जेस्ट अधिकारी थीं जोना करियर शुरू करने से लेकर केंद्र में सचिव पद पर काम करने वाले सभी अधिकारी योग्यांशी से ही थे। यहां एक बात और समझने की जरूरत है कि जहां तक केंद्र सरकार के पदों में ओबीसी को आरक्षण की बात है तो यह 1993 में पेश किया गया था और इसके तहत पहली नियुक्ति पाने वाले अधिकारीयों 1995 बैच के थे जोकि अब तक सचिव रैंक तक नहीं पहुंचे हैं। देखा जाये तो किसी भी आर्जेस्ट अधिकारी थीं जोना करियर शुरू करने से लेकर केंद्र में सचिव पद पर काम करने वाले सभी अधिकारी योग्यांशी से ही थे। यहां एक बात और समझने की जरूरत है कि जहां तक केंद्र सरकार के पदों में ओबीसी को आरक्षण की बात है तो यह 1993 में पेश किया गया था और इसके तहत पहली नियुक्ति पाने वाले अधिकारीयों 1995 बैच के थे जोकि अब तक सचिव रैंक तक नहीं पहुंचे हैं। देखा जाये तो किसी भी आर्जेस्ट अधिकारी थीं जोना करियर शुरू करने से लेकर केंद्र में सचिव पद पर काम करने वाले सभी अधिकारी योग्यांशी से ही थे। यहां एक बात और समझने की जरूरत है कि जहां तक केंद्र सरकार के पदों में ओबीसी को आरक्षण की बात है तो यह 1993 में पेश किया गया था और इसके तहत पहली नियुक्ति पाने वाले अधिकारीयों 1995 बैच के थे जोकि अब तक सचिव रैंक तक नहीं पहुंचे हैं। देखा जाये तो किसी भी आर्जेस्ट अधिकारी थीं जोना करियर शुरू करने से लेकर केंद्र में सचिव पद पर काम करने वाले सभी अधिकारी योग्यांशी से ही थे। यहां एक बात और समझने की जरूरत है कि जहां तक केंद्र सरकार के पदों में ओबीसी को आरक्षण की बात है तो यह 1993 में पेश किया गया था और इसके तहत पहली नियुक्ति पाने वाले अधिकारीयों 1995 बैच के थे जोकि अब तक सचिव रैंक तक नहीं पहुंचे हैं। देखा जाये तो किसी भी आर्जेस्ट अधिकारी थीं जोना करियर शुरू करने से लेकर केंद्र में सचिव पद पर काम करने वाले सभी अधिकारी योग्यांशी से ही थे। यहां एक बात और समझने की जरूरत है कि जहां तक केंद्र सरकार के पदों में ओबीसी को आरक्षण की बात है तो यह 1993 में पेश किया गया था और इसके तहत पहली नियुक्ति पाने वाले अधिकारीयों 1995 बैच के थे जोकि अब तक सचिव रैंक तक नहीं पहुंचे हैं। देखा जाये तो किसी भी आर्जेस्ट अधिकारी थीं जोना करियर शुरू करने से लेकर केंद्र में सचिव पद पर काम करने वाले सभी अधिकारी योग्यांशी से ही थे। यहां एक बात और समझने की जरूरत है कि जहां तक केंद्र सरकार के पदों में ओबीसी को आरक्षण की बात है तो यह 1993 में पेश किया गया था और इसके तहत पहली नियुक्ति पाने वाले अधिकारीयों 1995 बैच के थे जोकि अब तक सचिव रैंक तक नहीं पहुंचे हैं। देखा जाये तो किसी भी आर्जेस्ट अधिकारी थीं जोना करियर शुरू करने से लेकर केंद्र में सचिव पद पर काम करने वाले सभी अधिकारी योग्यांशी से ही थे। यहां एक बात और समझने की जरूरत है कि जहां तक केंद्र सरकार के पदों में ओबीसी को आरक्षण की बात है तो यह 1993 में पेश किया गया था और इसके तहत पहली नियुक्ति पाने वाले अधिकारीयों 1995 बैच के थे जोकि अब तक सचिव रैंक तक नहीं पहुंचे हैं। देखा जाये तो किसी भी आर्जेस्ट अधिकारी थीं जोना करियर शुरू करने से लेकर केंद्र में सचिव पद पर काम करने वाले सभी अधिकारी योग्यांशी से ही थे। यहां एक बात और समझने की जरूरत है कि जहां तक केंद्र सरकार के पदों में ओबीसी को आरक्षण की बात है तो यह 1993 में पेश किया गया था और इसके तहत पहली नियुक्ति पाने वाले अधिकारीयों 1995 बैच के थे जोकि अब तक सचिव रैंक तक नहीं पहुंचे हैं। देखा जाये तो किसी भी आर्जेस्ट अधिकारी थीं जोना करियर शुरू करने से लेकर केंद्र में सचिव पद पर काम करने वाले सभी अधिकारी योग्यांशी से ही थे। यहां एक बात और समझने की जरूरत है कि जहां तक केंद्र सरकार के पदों में ओबीसी को आरक्षण की बात है तो यह 1993 में पेश किया गया था और इसके तहत पहली नियुक्ति पाने वाले अधिकारीयों 1995 बैच के थे जोकि अब तक सचिव रैंक तक नहीं पहुंचे हैं। देखा जाये तो किसी भी आर्जेस्ट अधिकारी थीं जोना करियर शुरू करने से लेकर केंद्र में सचिव पद पर काम करने वाले सभी अधिकारी योग्यांशी से ही थे। यहां एक बात और समझने की जरूरत है कि जहां तक केंद्र सरकार के पदों में ओबीसी को आरक्षण की बात है तो यह 1993 में पेश किया गया था और इसके तहत पहली नियुक्ति पाने वाले अधिकारीयों 1995 बैच के थे जोकि अब तक सचिव रैंक तक नहीं पहुंचे हैं। देखा जाये तो किसी भी आर्जेस्ट अधिकारी थीं जोना करियर शुरू करने से लेकर केंद्र में सचिव पद पर काम करने वाले सभी अधिकारी योग्यांशी से ही थे। यहां एक बात और समझने की जरूरत है कि जहां तक केंद्र सरकार के पदों में ओबीसी को आरक्षण की बात है तो यह 1993 में पेश किया गया था और इसके तहत पहली नियुक्ति पाने वाले अधिकारीयों 1995 बैच के थे जोकि अब तक सचिव रैंक तक नहीं पहुंचे हैं। देखा जाये तो किसी भी आर्जेस्ट अधिकारी थीं जोना करियर शुरू करने से लेकर केंद्र में सचिव पद पर काम करने वाले सभी अधिकारी योग्यांशी से ही थे। यहां एक बात और समझने की जरूरत है कि जहां तक केंद्र सरक

